दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 26 अप्रैल 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 206

महत्वपूर्ण एवं खास

लॉकडाउन के दौरान देश में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी

नई दिल्ली,(आरएनएस)। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को एक महीने हो गए हैं। सरकार के इस प्रभावशाली कदम से कोरोना के बढ़ने की रफ्तार में काफी कमी आई है। अगर एक दिन का आंकड़ा यानि शुक्रवार सुबह 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे तक देखे तो भारत में नए मामलों की वृद्धि दर 6 फीसदी है। यह भारत में 100 मामलों को पार करने के बाद से दर्ज की गई सबसे कम दैनिक वृद्धि दर है। सूत्रों की माने तो यदि देश में लॉकडाउन के दौरान पूरे महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो वायरस के फैलने की रफ्तार में भारी कमी देखने को मिलेगी. अगर सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाने के लिए केसों के बढ़ने का इंतजार किया होता तो आज हालात कुछ और ही होते। ऐसा अनुमान है कि अगर समय पर लॉकडाउन नहीं लगता तो देश में अभी तक 8 से 9 गुना ज?यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हो जाते। इस संख?या में यह आंकड़ा 2 लाख के पार हो सकता था। गौरतलब है कि देश में जब लॉकडाउन लगा था तब संक्रमित मरीजों की कुल संख?या लगभग 500 थी, उस समय कोरोना वायरस की डेली ग्रोथ लगभग 20 फीसदी थी। जबकि 25 अप्रैल को कोरोना के मामले 24000 से ज?यादा हो गए. हालांकि डेली ग्रोथ रेट में काफी कमी आई है और हर दिन वृद्धि लगभग 8 फीसदी रह गई है।

देश में हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्विन का बंपर स्टॉक

जरूरत से 10 गुना ज्यादा है भंडार

नई दिल्ली,(आरएनएस)। भारतीय ड्रग्स एसोसिएशन गुजरात के चेयरमैन विरंची शाह ने दावा किया है कि देश में हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्विन की कोई कमी नहीं है। हर महीने करीब 35 से 40 करोड़ गोलियों का उत्पादन हो रहा है। शाह ने कहा कि हम हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्विन की जितनी गोलियों का उत्पादन कर रहे हैं वह हमारी जरूरत का 10 गुना है। उन्होंने बताया कि दुनिया में हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के कुल उत्पादन का 70 फीसदी सिर्फ भारत में होता है। इस दवा का इस्तेमाल मूल रूप से मलेरिया और अर्थराइटिस के कुछ मामलों में किया जाता है। शाह ने बताया कि पिछले साल भारत में करीब 2.4 करोड़ गोरियों की खपत हुई थी। इस हिसाब से हमारे पास हर महीने जरूरत से 10 गुणा अधिक उत्पादन हो रहा है। शाह ने कहा, हम इस वक्त दूसरे जरूरतमंद देशों को भी हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने करीब दस करोड़ गोलियों का एक बफर स्टॉक रखा है जो लगभग 20 लाख कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त होगी।

रोटरी क्लब ऑफ ने पीआईबी के साथ मिल कर फेस मास्कों की आपूर्ति की

नईदिल्ली,(आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्तमान कोविड संकट के दौरान राहत सामग्री से देशवासियों की मदद करने के आह्वान पर रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली हेरिटेज ने पत्र सूचना कार्यालय के साथ मिल कर बड़े पैमाने पर वितरण के लिए दोबारा इस्तेमाल में आने वाले 50,000 फेस मास्कों की आपूर्ति की। रोटरी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय सेवा संगठन है जिसका उद्देश्य मानव सेवा और दुनिया भर में सद्भाव और शांति को आगे बढ़ाने में कारोबारियों और व्यावसायिक मार्गदर्शकों को एक साथ लाना है। वितरित किए गए फेस मास्क लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने घरों में काम करते समय महिला दर्जियों द्वारा बनाए गए हैं।

मैनहोल का ढक्कन चोरी करने पर होगी मौत की सजा

पेइचिंग,(आरएनएस) । चीन में मैनहोल का ढक्कन चुराने वालों की शामत आने वाली है। सुनने में भले ही यह अपराध आम लगे लेकिन इसके कारण होने वाले नुकसान को देखते हुए इसकी सजा मौत हो सकती है। चाइना डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2019 के बीच मैनहोल का ढक्कन हटाने या उसे नुकसान होने के कारण 70 हादसे हो चुके हैं। देश की सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरोटोरेट और पब्लिक सिक्यॉरिटी मंत्रालय ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में सख्त सजाएं जारी की हैं। एक अधिकारी के मुताबिक मैनहोल कवर को नजरअंदाज किया जाता है लेकिन वे लोगों की जिंदगियों, सेफ्टी और सिक्यॉरिटी से जुड़े होते हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने संजय कोठारी

राष्ट्रपति कोविंद ने दिलाई गोपनीयता एवं पद की शपथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सतर्कता (सीवीसी) के नए आयुक्त के तौर पर संजय कोठारी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले शनिवार को कोठारी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बातया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के तौर पर काम कर चुके संजय कोठारी ने आज सुबह साढ़े दस बजे आयोजित एक समारोह में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण की, जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण कराई। इस मौके पर उप राष्ट्रपति वेकैंया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में शामिल थे, जहां सभी लोग कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नजर आए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय चयन समिति ने फरवरी में कोठारी के नाम की अनुशंसा की थी।

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। सीवीसी प्रमुख का कार्यकाल चार वर्ष का या इसके मौजूदा प्रमुख की 65 वर्ष की आयु होने तक का होता है। सीवीसी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में सतर्कता आयुक्त शरद कुमार अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर काम कर रहे हैं। कोठारी की नियुक्ति के बाद भी आयोग में सतर्कता आयुक्त का एक पद रिक्त है। हरियाणा कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी कोठारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद से जून 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें नवंबर 2016 में लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) का प्रमुख नियुक्त किया गया था। कोठारी को जुलाई 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव पद पर नामित किया गया। इस बीच, केंद्र सरकार ने सोमवार को राष्ट्रपति के सचिव के तौर पर कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया। असम-मेघालय कैडर के 1980 बैच के आईएएस (सेवानिवृत्त) अधिकारी त्रिपाठी पीईएसबी के अध्यक्ष हैं।

कांग्रेस का विरोध

जिस समय कोठारी को सीवीसी के पद के लिए अनुशंसा की गई उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए अपनाई प्रक्रिया को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया था और फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की थी। कोठारी की नियुक्ति को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध बढ़ सकता है। उनकी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए फरवरी में कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन आमंत्रित करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी।

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं।

कोरोना के इलाज की टूटी उम्मीद, पहले ही ट्रायल में फेल हुआ ड्रग रेमडेसिवयर

वुहान ,(आरएनएस)। वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दवा/वैक्सीन की कमी का सामना कर रही दुनिया को एक और बड़ा झटका लगा है। बताया जाता है कि एंटी वायरल ड्रग रैंडम क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गया है। इस एंटी वायरल ड्रग का नाम रेमडेसिवयर है, जिसका टेस्ट चीन अपने देश के कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर कर रहा था। इसे लेकर दुनिया भर में उम्मीद थी। इस एंटी वायरल ड्रग का नाम रेमडेसिवयर है। चीनी ट्रायल में पता चला कि यह ड्रग नाकाम रही। रेमडेसिवयर ड्रग से मरीज में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। मतलब रेमडेसिवयर ड्रग देने से मरीज के खून में रोगाणु कम नहीं हुए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दस्तावेजों से इसकी जानकारी मिली है। इसके फेल होने की रिपोर्ट को डब्लूएचओ ने अपने वेबसाइट पर विस्तार से प्रकाशित किया था। बाद में इस रिपोर्ट को हटा दिया गया। इस पर सफाई देते हुए डब्लूएचओ ने कहा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट गलती से अपलोड हो गई थी इसलिए रिपोर्ट को हटा लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया था कि कुल 237 मरीजों में से कुछ को रेमडेसिवयर ड्रग दी गयी और कुछ को प्लेसीबो। एक महीने बाद रेमडेसिवयर लेने वाले 13.9त्न मरीजों की मौत हो गयी जबकि इसकी तुलना में प्लेसीबो लेने वाले 12.8प्रतिशत मरीजों की मौत हुई। ऐसी हालात में साइड इफेक्ट के कारण ट्रायल को पहले ही रोक दिया गया। इस ड्रग को बनाया है अमेरिका फर्म गिलिएड साइंस ने। एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिवयर के बारे में डब्लूएचओ ने गुरुवार को अपने साइट पर रिपोर्ट दी और बताया कि ये कारगर साबित नहीं हुई।

ब्रिटिश अधिकारियों ने अन्य बीमारियों को लेकर चिंता जाहिर की

लंदन,(आरएनएस)। ब्रिटिश चिकित्सा अधिकारियों ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना वायरस के अलावा अन्य बीमारियों के लक्षणों की अनदेखी न करें। यह बयान ऐसे समय आया है जब यह आशंकाएं सामने आ रही हैं कि पूरा ध्यान कोरोना वायरस महामारी की तरफ होने की वजह से कैंसर और अन्य बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा। 'पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड' ने कहा कि अप्रैल में अस्पताल के आपातकालीन विभाग में जाने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 50 फीसद कम हो गई है। परमार्थ कार्य करने वाले 'कैंसर रिसर्च यूके' का आकलन है कि हर हफ्ते बीमारी के 2,250 मामलों का पता ही नहीं चल पा रहा और इसकी एक वजह यह भी है कि लोगों को यह डर है कि अस्पताल जाने पर उन्हें वायरस का संक्रमण हो सकता है या फिर उन्हें अस्पतालों में पहले से ही मरीजों की अत्याधिक भीड़ की चिंता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) एक जन सूचना अभियान शुरू कर रहा है जिसमें लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि बेहद जरूरी होने पर मदद लें और कैंसर की जांच या मातृत्व संबंधी मामलों में नियमित समय पर जांच के लिये पहुंचें। उसने कहा कि अन्य बीमारियों के इलाज की गुंजाइश और क्षमता अभी बरकरार है। एनएचएस के मुख्य कार्यकारी सिमोन स्टीवंस ने कहा, समस्या की अनदेखी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, अभी या फिर भविष्य में।

लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था का लॉकआउट हुआ:कांग्रेस

सरकार से की राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस ने शनिवार को सरकार से आग्रह किया कि कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के समय में 'अर्थव्यवस्था का लॉकआउट' हो गया है और ऐसे में सरकार को कदम उठाने की जरूरत है।

सिब्बल ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप सलाह दीजिए, लेकिन कभी-कभी कांग्रेस पार्टी की सलाह भी ले लीजिए। कांग्रेस नेता के मुताबिक कोविड-19 के बाद नया हिंदुस्तान बनाना है। हम सब मिल जुलकर देश को आगे बढ़ाएं। उन मुद्दों पर ध्यान दें जो देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि इन पर उनकी योजना क्या है। सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है, यह कैसे होगा? हम तो बाहर की कंपनियों पर निर्भर हैं। ज्यादातर कर्पनियां तो बाहर हैं। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल का दाम 20 डॉलर हो गया है और पेट्रोल एवं डीजल की कीमत वही बनी हुई है। आप इसका फायदा जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि रोकने का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल किया कि यह कदम क्यों उठाया गया? उन्होंने आपदा मोचन अधिनियम-2005 का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून के मुताबिक एक राष्ट्रीय प्राधिकरण होता है जिसमें नौ मनोनीत सदस्य होते हैं इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

इसके तहत एक राष्ट्रीय योजना बनानी होती है। सिब्बल ने सरकार से आग्रह किया कि हमारी सलाह है कि जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय योजना बनाइए। सिब्बल के अनुसार इस कानून के तहत लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं भी लिखित हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने मूडीज और कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान का उल्लेख करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि भारत की विकास दर नकारात्मक रहेगी। इस स्थिति के लिए सरकार और प्रधानमंत्री को तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्यों के पास पैसे नहीं है और ऐसे में केंद्र को उन्हें धन मुहैया कराना चाहिए।

केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों का महंगाई भत्ते रोकने पर राहुल गांधी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह ने कहा है कि मौजूदा वक्त में सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मुश्किल में डालना गैरजरूरी है।

दक्षिण कोरिया में कोरोना के 10 नए मामले, मौत का कोई नया मामला नहीं

सियोल,(आरएनएस)। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के 10 नए मामले सामने आए हैं। यह लगातार आठवां दिन है जब देश में संक्रमण के मामले 20 से कम आए हैं। देश में शनिवार को लगातार दूसरे दिन मौत का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। दक्षिण कोरिया के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल मामले 10,718 हो गए और 240 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं।संक्रमण के मामलों में गिरावट आने के कारण दक्षिण अफ्रीका ने पिछले हफ्ते से लेकर अब तक सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों में थोड़ी ढील दी है। हालांकि प्रधानमंत्री चुंग से-क्युन ने ''गुपचुप'' तरीके से संक्रमण फैलने की आशंका पर चिंता जताई है और अधिकारियों को इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे दाएगू तथा आसपास के शहरों में एंटीबॉडी जांच करने के निर्देश दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सकें कि कोरोना वायरस का प्रसार कितना हो रहा है।चुंग ने महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान से उबरने के लिए मजबूत आर्थिक कदम उठाने का भी आह्वान किया। सरकार अहम उद्योगों में नौकरियों की रक्षा के लिए सरकारी बैंकों द्वारा जारी किए बॉन्ड्स के जरिए 32 अरब डॉलर की निधि जुटाने पर विचार कर रही है लेकिन इस योजना को संसद की मंजूरी की आवश्यकता है।

चीन में कोरोना के 49 गंभीर मामले, जनवरी बाद सबसे कम

बीजिंग,(आरएनएस)। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोनवायरस के कारण गंभीर स्थिति में केवल 49 लोग है जो जनवरी के अंत के बाद से सबसे कम आंकड़ा है। समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पिछले दिसंबर में वुहान में प्रकोप शुरू होने के बाद पहली बार, इनमें से कोई भी गंभीर कोविड-19 मामला शहर में दर्ज नहीं किया गया था, जहां वर्तमान में कोरोना संक्रमण के 23 मामले सक्रिय हैं।आयोग के अनुसार, मध्य रात्रि तक, 12 नए मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 11 आयातित मामले हैं।बाकी मामले स्थानीय हैं जो हेइलोंगजियांग प्रांत में सामने आए हैं, जो रूस की सीमा से लगता है और हाल के दिनों में रूस के यात्रियों के बीच संक्रमण पाया गया है जिससे चीन को

श्रीलंका में सोमवार से हटेगा देशव्यापी कर्फ्यू

कोलंबो,(आरएनएस)। श्रीलंका कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लगाए गए कर्फ्यू को सोमवार को हटा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि देश में संक्रमण के मामले 400 को पार कर गए हैं। देश में संक्रमण के सर्वाधिक 49 मामले शुक्रवार को दर्ज किए गए थे। श्रीलंका के नौसैन्य प्रतिष्ठान में कोविड-19 के 30 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़े हैं। देश में शुक्रवार तक संक्रमण के कुल 414 मामले थे। इनमें से 100 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं वहीं सात लोगों की मौत हो चुकी है।देश की पुलिस की ओर से शनिवार को जारी बयान के अनुसार 27 अप्रैल को सुबह पांच बजे से कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि कर्फ्यू फिर से लगाया जा सकता है और इस संबंध में सप्ताहांत में अधिकारी नया आदेश जारी कर सकते हैं। देश में 20 मार्च से 24 घंटे का कर्फ्यू लागू है। संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के कारण सरकार ने सोमवार को देशव्यापी कर्फ्यू में ढील देने का विचार त्याग दिया था और इसे 27 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था। कुछ क्षेत्रों में

गौड़ा ने रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स उद्योग को सबसे ज्यादा निर्यात करने पर बधाई दी

अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के बीच 2.68 लाख करोड़ का निर्यात

नईदिल्ली,(आरएनएस)। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स उद्योग को पहली बार देश का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बनने पर बधाई दी। उन्होंने भारत को रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन का एक अग्रणी वैश्विक केंद्र बनाने और विश्व में गुणवत्ता वाले रसायनों की आपूर्ति करने की दिशा में पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

इस उपलब्धि में अपने विभाग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए, गौड़ा अपने ट्वीट में कहा, मेरे रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण यह उद्योग पहली बार सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला क्षेत्र बन गया है।

उन्होंने बताया कि अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान, रसायनों के निर्यात में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान रसायनों का कुल निर्यात 2.68 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह कुल निर्यात का 14.35त्न है।

लॉकडाउन के बावजूद एनटीपीसी ने की निर्बाध बिजली आपूर्ति

नई दिल्ली,(आरएनएस)। कोरोना महामारी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी का राष्ट्र को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने में उसका मनोबल तोड़ने में नाकाम रही है। संकट की इस घड़ी में इनटीपीसी राष्ट्र को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रही है। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंह के सहयोग और मार्गदर्शन में इस महारत्न कंपनी के प्रत्येक विद्युत केन्द्र का प्रदर्शन अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।

कोविड-19 संकट ने बिजली कंपनी के महत्व को रेखांकित किया है और उनकी अहमियत अब काफी बढ़ गई है क्योंकि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के सुचारु संचालन के लिए बिजली काफी अहम है। एनटीपीसी बिजली की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए कोयले की आपूर्ति का प्रबंधन भी कुशलता के साथ कर रही है।

एनटीपीसी जहां 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है, वहीं कंपनी के सभी संयंत्रों में लॉकडाउन और सामाजिक दूरी से संबंधित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बिजली उत्पादन से इतर पीएसयू वंचित तबकों और प्रवासी कामगारों को राशन और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराकर सामाजिक कल्याण की गतिविधियों में भी व्यापक योगदान दे रही है। एनटीपीसी का प्रबंधन नियमित रूप से हर घटनाक्रम की निगरानी कर रहा है, जिससे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान देश के हर कोने में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति बनी रहे।

उसके विद्युत केन्द्रों में एनटीपीसी विंध्यांचल देश का सबसे बड़ा विद्युत केन्द्र है, जिसने 13 अप्रैल, 2020 को 100 प्रतिशत पीएलएफ हासिल किया और भारत के पहले अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल विद्युत केन्द्र एनटीपीसी खरगोन की दूसरी 660 मेगावाट की इकाई इस अवधि के दौरान व्यावसायिक हो गई, जिससे लॉकडाउन के बावजूद परिचालन के उत्कृष्टता की दिशा में एनटीपीसी की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

62,110 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी के 70 विद्युत केन्द्र हैं, जिनमें 24 कोयला, 7 संयुक्त गैस/ तरल ईंधन, 1 पनबिजली, 13 नवीकरणीय ऊर्जा के साथ 25 संयुक्त उपक्रम विद्युत केन्द्र हैं।